

## वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण 2014-15

### अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

हाल के वर्षों में अपनी आर्थिक सफलता को बनाए रखने के क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों को पार करना पड़ा है। इन चुनौतियों में प्रतिकूल बाहरी वातावरण, घरेलू स्तर पर अवसंरचनागत तनाव, मंद वृद्धि दर और स्फीतिकारी दबाव आदि प्रमुख थे। सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 की कारक लागत व स्थिर के मूल्यों पर) की वृद्धि में गिरावट में दृष्टव्य मंदी 2010-11 में 8.9 प्रतिशत थी जो अगले वर्षों 2011-12 तथा 2012-13 में घटकर क्रमशः 6.7 प्रतिशत तथा 4.9 प्रतिशत रह गई। 2013-14 में अर्थव्यवस्था में 4.9 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान के साथ ही वृद्धि में मंदी के रुझान प्रतिकूल हो गए। भारत में वृद्धि में मंदी मुख्य रूप से समान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के जैसी ही थी। वृद्धि में तेज गिरावट ने घरेलू कारकों और ग्लोबल आर्थिक माहौल की अनिश्चितताओं और कई समुन्नत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि को एक दूसरे से जोड़ा है। सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि ने 2011-12 की पहली तिमाही (क्यू-1) से ही मंदी का रुझान बनाए रखा था और सेवाओं में वृद्धि तथा उद्योगों में दीर्घकालिक मंदी ही इसकी विशिष्टता थी। स्थिर मानसून और वित्तीय तथा कारोबारी सेवा के क्षेत्र में सुस्पष्ट वृद्धि के चलते 2013-14 में वृद्धि ने रफ्तार पकड़ी।

आर्थिक मंदी के दौर में राजकोषीय उत्प्रेरण का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि 2010-11 के बाद स्फीति के उन्नत स्तर ने राजकोषीय गुंजाइश का संकेत पहले ही दे दिया था। निवेश में मंदी, सिग्नल प्राप्त परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब आदि कारणों के अलावा उभरता हुआ गत्यावरोध आदि कारणों और नए सुधारों को संरचनात्मक बाधाओं ने विकास को और भी अधिक उलझाया है। केंद्रीय बजट 2013-14 में अन्य बातों के साथ-साथ स्फीतिकारी दबावों के प्रभाव और वृद्धि सम्बन्धी संरचनात्मक गत्यावरोध पर काफी ध्यान दिया गया है।

वृद्धि में मौजूदा मंदी के जवाब में सरकार की नीतियों ने अवसंरचनात्मक सुधारों का एक खाका तैयार किया है। जिसका उद्देश्य एन्ट्री स्तर की बाधाओं को कम से कम करना और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ाना, राजकोषीय समेकन और प्रशासित मूल्यों में सुधार, वित्तीय/बैंकिंग क्षेत्रों को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना, आमजन में वित्तीय बचतों को बढ़ावा देने के लिए नई लिखतों को आरम्भ करना, अवसंरचना वित्तपोषण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज़) के जरिए अवसंरचनात्मक वित्तपोषण की सहायता के लिए निवेश चक्र को नए सिरे से शुरू करने वाले उपायों पर अमल करना, विनिर्माण वृद्धि को बहाल करने के लिए उपाय करना तथा ऊर्जा मूल्यन में सुधार लाना आदि

है। इन नीतियों ने हाथों-हाथ जाकर वृहद आर्थिक सुस्थरीकरण किया है जिसने स्फीति के सरोकारों को सन्तुलित बनाया है और वृद्धि को बहाल किया है, ऐसा करते हुए 2013-14 की दूसरी तिमाही (क्यू-2) में रुपए के मूल्य में तेज गिरावट के साथ-साथ बाहर के अस्थिर हालातों का सामना किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति स्फीति को रोकने, मिली जुली विदेशी आर्थिक स्थिति का प्रबन्धन करते समय बढोत्तरी बनाए रखने की अनिवार्यता द्वारा चालित होती है। समग्र शीर्ष स्फीति में सुधार के साथ-साथ थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार 2012-13 तथा 2013-14 की पहली दो तिमाहियों में यहां मई 2013 में 25 आधार बिन्दुओं तक की कमी की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 7.56 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान शीर्ष डब्ल्यूपीआई स्फीति का औसत 6.16 प्रतिशत रहा। इसके अलावा स्फीति दर, खासकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में उच्च थी।

वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के दौर में मौद्रिक सहजता जून 2013 में स्थिर हो गई थी। तथापि तब बाहरी स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार रहा था। निर्यात में तेजी और आयात में गिरावट के साथ ही वर्ष 2013-14 (अप्रैल-दिसम्बर) का व्यापार घाटा काफी कम हो गया था। व्यापार घाटे में घटोत्तरी पूरी तरह से निवल परोक्ष प्राप्तियों के रूप में हासिल उल्लेखनीय वृद्धि थी। जिसके फलस्वरूप 2013-14 की पहली तिमाही में चालू लेखा घाटा (सीएडी) में उल्लेखनीय कमी आई थी। इन विकास क्रमों के प्रत्युत्तर में, और सीएडी को उदार बनाए रखने की दिशा में उठाए गए कदमों के मद्देनजर, विनिमय दर जो कि अगस्त 2013 में पहले 68 रुपए प्रति अमरीकी डालर तक जा पहुंची थी, घटकर 11 अक्टूबर 2013 में 61.16 रुपए प्रति अमरीकी डालर रह गई थी। दिसम्बर 2013 में रुपए की औसत विनिमय दर प्रति अमरीकी डालर ₹ 61.91 हो गई थी।

राजकोषीय स्तर पर देखें तो वृद्धि में व्याप्त मंदी ने कर-संग्रहणों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त प्राप्तियों को प्रभावित किया है, तथापि सरकार 2013-14 में लक्षित जीडीपी के स्तर तक राजकोषीय घाटे को हासिल करने की दिशा में अनवरत रूप से प्रयत्नशील है।

### स.घ.उ. वृद्धि

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2013-14 में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर रजिस्टर करने का अनुमान लगाया गया है (स्थिर मूल्यों पर घटक लागत पर सघउ के अनुसार)। यह वृद्धि

2004-05 से 2013-14 के दौरान 7.6 प्रतिशत की दशकीय औसत की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम है। 2013-14 में अर्थव्यवस्था की 5 प्रतिशत से कम वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर गिरावट जिसमें 2013-14 में 0.7 प्रतिशत के विकास होने का अनुमान लगाया गया है और सेवा क्षेत्र के व्यापार, होटल, परिवहन और संचार खण्डों में कम वृद्धि का परिणाम है। सकारात्मक पक्ष में, क्षेत्र अर्थात् कृषि, बिजली, गैस और जलापूर्ति, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं और समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में 2012-13 के मुकाबले में 2013-14 में अधिक दर से वृद्धि होना लक्षित किया गया है।

अर्थव्यवस्था में इस वर्ष की पहली तिमाही में 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 की दूसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ साधारण तेजी दर्ज की गई। अग्रिम अनुमानों द्वारा पूर्ण वर्ष लिए लक्षित 4.9 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले, वर्तमान वर्ष की पहली छमाही में प्राप्त की गई 4.6 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष की दूसरी छमाही में आगे प्रति प्राप्ति भी दर्शाती है।

मांग पक्ष में, स्थिर बाजार मूल्यों पर सघउ 2012-13 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2013-14 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने का लक्ष्य किया गया है। 2013-14 के दौरान वास्तविकता में उपभोग व्यय, सकल नियत पूंजी निर्माण और निर्यात की वृद्धि क्रमशः 4.4 प्रतिशत, 0.2 प्रतिशत और 8.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2012-13 में इन घटकों में वृद्धि क्रमशः 5.2 प्रतिशत, 0.8 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया गया है। सीएसओ द्वारा जारी किये गए प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्यों (बचत दर) पर सघउ के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतें 2011-12 में 31.3 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 30.1 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट मुख्य रूप से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में बचतों की कमी द्वारा और भौतिक आस्तियों में परिवारों द्वारा बचतों के कारण है।

### कृषि उत्पादन

भारत में कृषि उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा प्रभावित किया जाता है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किये गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार (22.07.2013 की स्थितिनुसार) खाद्य उत्पादन 2011-12 (अंतिम अनुमान) में 259.29 मिलियन टन के मुकाबले 2012-13 में 255.36 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है।

2013 के दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के दौरान, देशभर में दीर्घावधि औसत (एलपीए) की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। कृषि मंत्रालय द्वारा 24.09.2013 को जारी किये गए प्रथम अग्रिम अनुमानों (केवल खरीफ फसलों को कवर करके) के अनुसार, 2013-14 के दौरान खाद्य अनाजों का उत्पादन 129.32 मिलियन टन (चावल 92.32 मिलियन टन) रहा है। दालों का खरीफ उत्पादन

6.01 मिलियन टन, गन्ने का 341.77 मिलियन टन, तिलहन 23.96 मिलियन टन और कपास 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की 35.30 मिलियन गांठें होने का अनुमान लगाया गया है।

कृषि ऋण प्रवाह 2003-04 में ₹ 86,981 करोड़ और 2011-12 में ₹ 5,11,029 करोड़ की तुलना में 2012-13 में बढ़कर 6,07,375 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया है। 2013-14 के लिए कृषि ऋण प्रवाह बढ़ाकर ₹ 7,00,000 करोड़ कर दिया गया है।

### कीमतें

2013-14 (अप्रैल-दिसंबर) में मुख्य थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 7.56 प्रतिशत की तुलना में यह औसतन 6.16 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2013-14 की शुरुआत में मुख्य थोक मूल्य सूचकांक 4.77 प्रतिशत रहा और नवम्बर 2013 में 7.52 प्रतिशत से गिरकर, दिसंबर 2013 में 6.16 प्रतिशत रहा है।

कोर (गैर-खाद्य विनिर्माण) मुद्रास्फीति भी धातुओं और रसायनों में मुद्रास्फीति में गिरावट द्वारा सामान्य वापसी के चिन्हों को दर्शा रही है। यह अगस्त 2012 में 5.77 के शीर्ष से घटकर दिसम्बर 2013 में 2.81 प्रतिशत हो गई।

समग्र थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति जिसमें प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद शामिल होते हैं, पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 9.03 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 (अप्रैल-दिसम्बर) में औसतन 10.54 प्रतिशत रही। दिसम्बर 2013 में, खाद्य में मुद्रास्फीति दबावों में कुछ कमी दर्शाते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति दिसम्बर 2012 में 9.96 प्रतिशत और नवम्बर 2013 में 13.81 प्रतिशत की तुलना में 9.47 प्रतिशत थी। जबकि खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, इसके प्रेरक समय-समय पर बदलते रहे हैं। 2012-13 में, मुद्रास्फीति अनाजों, दालों, सब्जियों, अंडें, मांस और मछली, चीनी और खाद्य तेल आदि सहित खाद्य के सभी प्रमुख उपसमूहों हेतु समग्र में उच्च बनी रही। तथापि, वर्तमान वर्ष में, प्राथमिक योगदान में अनाज, सब्जियां और अण्डा, मांस और मछली शामिल हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संदर्भ में मापित मुद्रास्फीति चालू वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उच्च स्तरों पर बनी रही। खाद्य मदों, जिनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में तुलनात्मक रूप से अधिक भारांश होता है, की मुद्रास्फीति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर पर रखा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - नई श्रृंखला (सीपीआई-एनएस) की अखिल भारतीय सामान्य मुद्रास्फीति 2013-14 (अप्रैल-दिसंबर) में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 10.04 प्रतिशत की तुलना में औसतन 9.87 प्रतिशत रही। सकारात्मक पक्ष है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-नई श्रृंखला के अनुसार मुद्रास्फीति नवंबर 2013 में 11.16 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2013 में 9.87 प्रतिशत पर आ गई है।

मुद्रास्फीति घटाने के लिए विभिन्न राजकोषीय, मौद्रिक और प्रशासनिक उपाय किए हैं। पहले ही चल रहे कुछ विशिष्ट उपायों में ये शामिल हैं: गेहूं, प्याज और दालों पर से आयात शुल्क कम करना, कुछ महत्वपूर्ण खाद्य तेलों और दालों का निर्यात रोकना, चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के मामले में स्टॉक सीमाएं लगाना, वर्ष 2002 से चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य बनाए रखना (बीपीएल के लिए ₹ 5.65 प्रति किलोग्राम और एएवाई के लिए ₹ 3 प्रति किलोग्राम) और गेहूं (बीपीएल के लिए ₹ 4.15 प्रति किलोग्राम और एएवाई हेतु ₹ 2 प्रति किलोग्राम), चावल, उड़द और तुर का वायदा कारोबार निलंबित रखना, खुली बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत चावल और गेहूं का आवंटन, आदि।

### उद्योग और सेवाएं

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आआईपी) (आधार: 2004-05) औद्योगिक उत्पादन का अग्रणी सूचकांक है। आईआईपी के अनुसार औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल-नवंबर, 2013 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 0.9 प्रतिशत की तुलना में (-) 0.2 प्रतिशत थी। वैश्विक और घरेलू कारकों के संयोजन से औद्योगिक उत्पादन में मंदी रही है। चालू वर्ष के दौरान वृद्धि में गिरावट मुख्यतया खनन क्षेत्र, पूंजीगत सामान और उपभोक्ता वस्तुओं में मंदी के कारण हुई है। उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र विनिर्माण ने अप्रैल-नवंबर 2013 के दौरान पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.6 प्रतिशत की कमी देखी गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान विनिर्माण उत्पादन 1.3 प्रतिशत बढ़ा था।

विनिर्माण में सुस्ती के अनेक कारण हैं। मुद्रास्फीति काबू में लाने की जरूरत से आवश्यक हुई नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ बड़ी परियोजनाओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों ने निवेशों पर असर डाला। सकल नियत पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 2010-11 की पहली तिमाही के आसपास मंद रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विनिर्माण ने मूल्य कड़ी अतिसमय को नहीं बढ़ाया। अनुसंधान और विकास में निवेश के निम्न स्तर के कारण रसायन, मशीनरी और उपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जैसे वैश्विक बाजार में उच्च और मध्यम प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ नहीं उठाया।

हाइडल स्रोतों से बिजली के उत्पादन में संतुलित वृद्धि के कारण समग्र बिजली उत्पादन में वृद्धि अप्रैल-नवंबर 2013 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 4.4 प्रतिशत की तुलना में 5.4 प्रतिशत हुई है। ढांचागत अवरोधों के कारण खनन क्षेत्र में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 1.6 प्रतिशत की मंदी की तुलना में इसका समग्र औद्योगिक उत्पादन घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का उत्पादन अप्रैल-नवंबर 2013 के दौरान पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 11.3 प्रतिशत की मंदी की तुलना में कम होकर 0.1 प्रतिशत रह गई है जो इंगित करता

है कि इस क्षेत्र में मंदी समाप्त होनी शुरू हो गई है। खनन और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में नकारात्मक गिरावट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की कम मांग के कारण भी समग्र विनिर्माण वृद्धि में गिरावट हुई है।

### विदेशी क्षेत्र

भारत का निर्यात 2011-12 में बढ़कर 21.8 प्रतिशत हो गया और 2012-13 में सिकुड़ कर 1.8 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान निर्यात 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) में 217.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 230.3 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का हो गया। आयात का मूल्य अप्रैल-दिसंबर 2013 के दौरान 2012-13 की तदनु रूप अवधि में 364.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में 6.6 प्रतिशत गिरावट दर्शाते हुए 340.4 बिलियन अमरीकी डालर था। कुल आयातों में पीओएल के आयात अप्रैल-दिसंबर 2013 में 125.0 बिलियन अमरीकी डालर (36.7 प्रतिशत) बैठते हैं। यह 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) में 121.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 2.6 प्रतिशत अधिक था। पीओल-भिन्न आयात 2013-14 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 215.4 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का था जो 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) में 242.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 11.1 प्रतिशत कम था। निर्यात में बेहतर परिणाम और आयातों में कमी के कारण व्यापार घाटा 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) में 146.8 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2013-14 (अप्रैल-दिसंबर) में 110.0 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया।

जबकि अप्रैल-दिसंबर, 2013 की अवधि के लिए वाणिज्य व्यापार पर डाटा उपलब्ध है, भुगतान क्षेत्र से संबंधित सर्वाधिक सूचना केवल 2013-14 की पहली छमाही के लिए उपलब्ध है। 2012-13 की प्रथम छमाही में 91.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2013-14 की प्रथम छमाही में व्यापार घाटा 83.8 मिलियन था। निवल अदृश्य आय 2012-13 में 53.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 56.8 बिलियन अमरीकी डालर थी। निवल अदृश्य प्राप्ति में वृद्धि के साथ व्यापार घाटे में संकुचन से 2012-13 की प्रथम छमाही में 38.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2013-14 की प्रथम छमाही में 27.0 बिलियन अमरीकी डालर तक चालू खाता घाटा कम हो गया।

पूंजी तथा वित्तीय खाते के अंतर्गत निवल अंतर्वाह पोर्टफोलियो निवेश के निवल बहिर्वाह के कारण 2012-13 की प्रथम छमाही में 37.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2013-14 की प्रथम छमाही में 15.1 बिलियन अमरीकी डालर तक कम हो गये। 2013-14 के पूर्वार्ध के दौरान चालू खाता घाटा कम रहने के बावजूद मुख्यतः निवल पूंजी अंतर्वाह में कमी आने के कारण 2012-13 के पूर्वार्ध में 0.4 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में विदेशी मुद्रा भण्डार में 10.7 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई।

2013-14 में, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां 275.5 बिलियन अमरीकी डालर से 293.9 बिलियन अमरीकी डालर की रैंज में रही हैं। दिसंबर, 2013 के अंत में, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां 293.9 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो मार्च, 2013 के अंत में 292 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 1.9 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाती हैं।

अप्रैल, 2013-दिसंबर, 2013 के दौरान, रुपए की मासिक औसत विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ पर) प्रति अमरीकी डालर ₹ 54-64 की रैंज में थी। रुपए की दैनिक विनिमय दर अगस्त 2013 में प्रति अमरीकी डालर ₹ 68 के स्तर पर भंग हो गयी (28 अगस्त, 2013 में प्रति डालर ₹ 68.36)। तथापि, यह 11 अक्टूबर, 2013 में प्रति डालर ₹ 61.16 तक सुधर गयी, जो सीएडी को नियंत्रित करने तथा पूंजीगत प्रवाहों को तेज करने के लिए किए गए उपायों का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। महीना-दर-महीना आधार पर, मार्च 2013 में 54.40 प्रति डालर से दिसंबर, 2013 में 61.91 प्रति डालर तक रुपए का 12.1 मूल्य ह्रास हुआ है।

सितंबर 2013 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण स्टॉक 400.3 बिलियन अमरीकी डालर था जिसने मार्च, 2013 के अंत में स्तर की तुलना में 9 बिलियन अमरीकी डालर की कमी दर्ज की है।

### मुद्रा बैंकिंग और पूंजी बाजार

भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मई, 2013 को अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण में शीर्ष मुद्रास्फीति की क्रमिक मंदी के चरण में वृद्धि की सहायता के लिए 7.50 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत तक और अधिक 25 बीपीएस की नीति रेपोदर में कमी की घोषणा की। मई 2013 के बाद में अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा मात्रात्मक सुखद (क्यूई) के कम होने की संभावना की आशंका ने पोर्टफोलियो के निवेश का बहिर्वाह तेज किया है। विदेशी घटनाक्रमों से अर्थव्यवस्था में जोखिमों को मान्यता देते हुए तथा उदीयमान वृद्धि मुद्रास्फीति गतिकी को में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जुलाई, 2013 की प्रथम तिमाही समीक्षा में मुख्य नीतिगत दरों को स्थिर रखा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितंबर, 2013 को मध्य तिमाही समीक्षा में विदेशी माहौल में सुधार का ध्यान रखते हुए तथा सीएडी को कम करने और इसके वित्तपोषण को आसान बनाने के लिए कार्यरत उपायों पर विचार करते हुए विनिमय बाजार दबावों से निपटने के लिए प्रारंभ किए गए आपवदिक नकदी उपायों की अंशशोधित वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ की। एमएसएफ दर 75 आधार बिंदु कम करके 10.25 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत की गई तथा सीआरआर का न्यूनतम दैनिक अनुस्क्षण 21 सितंबर, 2013 के प्रारंभिक पक्ष से 99 प्रतिशत की जरूरत से 95 प्रतिशत प्रभावी तक कम किया गया। तथापि, मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा रुपये के आंतरिक मूल्य के परिक्षण में सहायता हेतु नाममात्र का स्थिरीकरण प्रदान करने की जरूरत हेतु रेपोदर 25 आधार बिंदु बढ़ा करके 7.5 प्रतिशत कर दी गई।

उदीयमान नकदी स्थिति पर विचार करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 आधार बिंदु कम करके एमएसएफ दर 7 अक्टूबर, 2013 को 9.5 प्रतिशत से 9.00 प्रतिशत कर दी। 11 अक्टूबर, 2013 से प्रारंभ प्रत्येक शुक्रवार को परिवर्तनीय दर नीलामियों के जरिए बैंकिंग प्रणाली की 0.25 प्रतिशत निवल मांग और समयबद्ध देनदारियों (एनडीटीएल) के समतुल्य अधिसूचित राशि के लिए 7 दिन तथा 14 दिन की अवधि की आवधिक रेपो के जरिए अतिरिक्त नकदी के प्रावधान की घोषणा की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, 29 अक्टूबर, 2013 की द्वितीय तिमाही समीक्षा में एमएसएफ दर को 25 बीपीएस कम करके 9.00 प्रतिशत से 8.75 प्रतिशत तक घटाने के साथ अंशशोधित कम न होने वाले आपवादिक उपायों को आगे बढ़ाया। म्यूचुअल फंड की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को सक्षम बनाने हेतु जुलाई, 2013 को संस्थापित म्यूचुअल फंड की स्पेशल रेपो विंडो भी बंद कर दी गई। इन संकेतों के साथ कि थोक तथा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दोनों अगले महीनों में बढ़े रहने की संभावना है, मुख्य नीति रेपो दर 25 आधार बिंदु बढ़ा करके 7.50 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत कर दी गई। नकदी की स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रणाली में नकदी प्रदान करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, एमएसएफ दर में कमी में अतिरिक्त, 7-दिवस तथा 14 दिवस की अवधि की आवधिक रेपो के जरिए प्रदान की गई नकदी बैंकिंग प्रणाली को एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दी गयी थी।

ये उपाय बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और कमजोर विकास की परिस्थिति में मुद्रास्फीति की संभावनाओं का प्रबंध करने के लिए किए गए थे।

वैश्विक प्रवृत्ति की तर्ज पर भारतीय पूंजी बाजार यूएस फेडरल प्रारक्षित के मासिक बांड खरीद कार्यक्रम के कमतर होने संबंधी बाजार भागीदारों की संभावना द्वारा प्रभावित हुआ था। तथापि, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निवेशक अनुकूल उपायों ने भारतीय बाजार में निवेशकों के रुझान को सकारात्मक बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय पूंजी बाजार वर्ष 2013 में अन्य उभरते बाजारों की तुलना में विश्व के एक बेहतर बाजार के रूप में उभरा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी भारतीय बाजार में अपना विश्वास बनाए है, जो 2013 के अंतिम चार महीनों के दौरान सकारात्मक विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश से उजागर हुआ है, जो मौजूदा वर्ष में जून-अगस्त की अवधि के दौरान निवल बहिर्वाह की पहले की प्रवृत्ति के विपरीत हुआ है। वर्ष 2013 में भारत में कुल निवल एफआईआई प्रवाह 12.13 अमरीकी डालर था (+) इक्विटी में 20.10 बिलियन और (-) ऋण में 7.97 बिलियन), निवेश का रुझान मुख्य रूप से इक्विटी प्रवाहों से उत्प्रेरित था।

## सरकार के वित्त साधन

संकट के बाद राजकोषीय सुदृढीकरण के दौर में भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 को छोड़कर राजकोषीय घाटा के बजटीय स्तर का कड़ाई से पालन किया, जब राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत, बजट अनुमानों से 1.1 प्रतिशत बिन्दु अधिक था। प्रतिकूल वृहद् - आर्थिक घटनाक्रम, विशेष कर 2011-12 की समग्र आर्थिक गिरावट 2012-13 के दौरान भी जारी रही, जिसने सरकार को सुधार पर और अधिक जोर देने के लिए मजबूर कर दिया। केन्द्रीय सरकार ने केलकर समिति (राजकोषीय सुदृढीकरण हेतु कार्य योजना पर) द्वारा अनुशंसित, सुधारों को कार्यान्वित किया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5.1 प्रतिशत के बजटीय स्तर से कम था।

विकास में, विशेषकर विनिर्माण में गिरावट और 2013-14 के पूर्वार्ध में वित्तीय बाजार में मन्द रुझान ने राजकोषीय मोर्चे पर दबाव डाला, शेषकर कर संग्रहण और विनिवेश प्राप्तियों पर। ऋण-भिन्न प्राप्तियों की वर्षनुवर्ष वृद्धि में कमी और संशोधित अनुमान 2012-13 की तुलना में ब.अ. 2013-14 में निहित वृद्धि के संबंध में 2013-14 के पूर्वार्ध में कुल व्यय में मामूली उच्च वर्षानुवर्ष वृद्धि के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप 2013-14 के पूर्वार्ध में अधिक राजकोषीय घाटा हुआ।

अप्रैल-दिसंबर 2013 के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केन्द्रीय सरकार के वित्त संबंधी आंकड़ों के अनुसार बजट 2013-14 में परिकल्पित विकास की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। अप्रैल-दिसंबर 2013 में सकल कर राजस्व वर्षनुवर्ष 9.2 प्रतिशत बढ़कर ₹ 7,43,709 करोड़ हो गया। वृद्धि का यह स्तर अप्रैल-दिसंबर 2012 में 15.0 प्रतिशत और ब.अ. 2013-14 में परिकल्पित विकास से कम है। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में अप्रैल-दिसंबर 2013 में सकल कर राजस्व 60.2 प्रतिशत था, जो पिछले पांच वर्ष के औसत से कम था। अप्रैल-दिसंबर 2013 में कर-भिन्न राजस्व ₹ 1,16,272 करोड़ है, जो बजट अनुमान का 67.5 प्रतिशत और पिछले पांच वर्ष के औसत से बहुत कम है। ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में अप्रैल-दिसंबर 2013 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण कमी आयी, यह कमी मुख्यतः विनिवेश प्राप्तियों के कारण आयी क्योंकि बजट व्यवस्था की गई 55,814 करोड़ रुपए की राशि का केवल ₹ 5,430 करोड़ की वसूली की गई।

व्यय के मोर्चे पर संशोधित अनुमान 2012-13 की तुलना में ब.अ. 2013-14 द्वारा परिकल्पित 16.4 प्रतिशत अंतर्निहित वर्षनुवर्ष वृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2013 में कुल व्यय में वृद्धि 17.4 प्रतिशत रही है। ब.अ. के अनुपात के रूप में, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय अप्रैल-दिसंबर 2013 में 73.6 प्रतिशत है, जो 77.6 प्रतिशत के पांच वर्ष के औसत से कम है। तथापि, अप्रैल-दिसंबर 2013 में मुख्य सव्बिडियों में तेजी से वृद्धि हुई और ₹ 1,88,899 करोड़ के आंकड़े (ब.अ. का 85.5 प्रतिशत) तक पहुंच गया।

2013-14 के लिए बजट में राजकोषीय घाटे का स्तर ₹ 5,42,499 करोड़ होने का अनुमान है। अप्रैल-दिसंबर 2013-14 में घाटे के लक्ष्य में फिसलन मुख्यतः ऋण-भिन्न प्राप्तियों में फिसलन के कारण हुआ। योजना खर्च में अतिरिक्त प्रारम्भिक व्यय (फ्रंट लोडिंग) और निम्न कर और अन्य प्राप्तियों के कारण बजट अनुमान के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा अप्रैल-दिसंबर 2013 में 95.2% रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। तथापि, व्यय के योक्तिकीकरण और बचे हुए संशोधनों के सम्मिलित प्रयासों सहित समेकन हेतु सक्रिय राजकोषीय नीति अवस्थिति के चलते सरकार पुनः समेकन लक्ष्यों में जुट गई। संशोधित अनुमान 2013-14 में राजकोषीय और राजस्व घाटा क्रमशः सघट का 4.6% और 3.3% रखा गया है जो राजकोषीय विवेक की ओर सरकार की पक्की वचनबद्धता की पुनर्पुष्टि करता है।

## संभावनाएं

जनवरी, 2014 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी दि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में 2013 और 2014 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास अनुमान में मामूली रूप से संशोधन करके क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत किया गया है। 2014 के बाद मध्यम अवधि की तुलना में वैश्विक विकास संभावनाओं में धीरे-धीरे सुधार होने का अनुमान लगाया गया है। भारत में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनेक बड़ी निवेशी परियोजनाओं को मंजूरी देने सहित अनेक सुधार के उपाय किए गए हैं। इन उपायों से निवेश के पुनरुद्धार और अर्थव्यवस्था में विकास हेतु सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त निर्यात के पुनरुत्थान, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार की संभावनाएं और हाल में देखी गई मुद्रास्फीति में नरमी, 2013-14 की तुलना में 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर परिदृश्य का संकेत देते हैं।

**वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण**  
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
<b>संपदा क्षेत्र</b>					
1.	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ( ₹ हजार करोड़)*				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	9389 <sup>1</sup> आर	10540 <sup>ए</sup>	11.9 <sup>1</sup> आर	12.3 <sup>ए</sup>
	(ख) 2004-2005 के मूल्यों पर	5482 <sup>1</sup> आर	5749 <sup>ए</sup>	4.5 <sup>1</sup> आर	4.9 <sup>ए</sup>
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2004-05=100) <sup>^</sup>	166.8	166.5	0.9	-0.2
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100) @	166.7	176.9	7.56	6.16
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:औद्योगिक कामगार (2001=100) @	212.7	235.3	10.00	10.66
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) ( ₹ हजार करोड़)\$	8032	9228	11.2	14.9
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) ₹ करोड़	1983941	2036568	15.7	2.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	364242	340378	0.1	-6.6
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात **				
	(क) ₹ करोड़	1184749	1386496	11.1	17.0
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	217415	230336	-4.0	5.9
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)**	-146827	-110042	6.9	-25.1
9.	विदेशी मुद्रा भंडार				
	(क) ₹ बिलियन में	16194.23	18190.09	2.5	12.3
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर में	295.6	293.9	-0.4	-0.6
10.	चालू लेखा शेष (मिलियन अमरीकी डालर में)(अप्रैल-सितंबर)	-38.2	-27.0	-	-
<b>सरकारी वित्त साधन #</b>			₹ करोड़		
1.	राजस्व प्राप्तियां	570536	633933	14.5	11.1
2.	कर राजस्व (निवल)	484156	517661	15.2	6.9
3.	कर-भिन्न राजस्व	86380	116272	10.6	34.6
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	420587	529858	5.7	26.0
5.	ऋणों की वसूली	7710	8038	-45.4	4.3
6.	अन्य प्राप्तियां	8178	5430	198.1	-33.6
7.	उधार और अन्य देनदारियां	404699	516390	6.2	27.6
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	991123	1163791	10.6	17.4
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	695233	812528	12.2	16.9
10.	राजस्व खाता	625598	731159	13.6	16.9
<i>जिसमें:</i>					
11.	ब्याज भुगतान	201959	248464	12.6	23.0
12.	पूंजी खाता	69635	81369	1.3	16.9
13.	आयोजना व्यय	295890	351263	6.9	18.7
<i>जिसमें:</i>					
14.	राजस्व खाता	242975	274016	3.9	12.8
15.	पूंजी खाता	52915	77247	23.1	46.0
16.	कुल व्यय (9+13)	991123	1163791	10.6	17.4
17.	राजस्व व्यय (10+14)	868573	1005175	10.7	15.7
18.	पूंजी व्यय (12+15)	122550	158616	9.6	29.4
19.	राजस्व घाटा (17-1)	298037	371242	4.2	24.6
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	404699	516390	6.2	27.6
21.	प्राथमिक घाटा (20-11)	202740	267926	0.6	32.2

1आर: पहला संशोधित अनुमान

^ अप्रैल से नवम्बर

अ.अ. अग्रिम अनुमान

\* पूर्ण वर्ष से संबंधित

@ अप्रैल से दिसम्बर की औसत

\$ एम<sub>3</sub> संबंधी आंकड़े वर्ष 2012-13 के लिए 28 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार और 2013-14 के लिए 27 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं।

\*\* सीमाशुल्क आधार पर, चालू वर्ष हेतु संशोधित आधार की तुलना में अनन्तिम आधार पर।

# लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।